न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और मदन मोहन पुंछी, जे. के समक्ष

नसीब सिंह,-याचिकाकर्ता
बनाम
मामन और अन्य,-प्रतिवादी

1979 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 396
1 नवंबर, 1979

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का 2) - धारा 169, 173 और 190 - किसी मामले की जांच जिसमें कोई अपराध न हो - पुलिस मामले को रद्द करने के लिए धारा 169 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है - ऐसा मजिस्ट्रेट - क्या वह इसका संज्ञान लेने में सक्षम है धारा 190 (1) (ए) और (बी) के तहत अपराध और आरोपी के खिलाफ फिर से प्रक्रिया जारी करें।

माना गया कि एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190 (1) (सी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान तभी ले सकता है, जब उसे इसकी जानकारी हो। उस ज्ञान को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट से या उसके बिना प्राप्त किया जा सकता है ताकि नए सीओडी की धारा 190 (1) (सी) के तहत संज्ञान की नींव लाई जा सके। वही उद्देश्य एसयूएल धारा के खंड (बी) के तहत भी प्राप्त किया जा सकता है। (1) संहिता की धारा 190 में जब किसी पुलिस रिपोर्ट को धारा 173 (2) के तहत खारिज कर दिया जाता है, तो उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होता है कि क्या अन्य विवरण बताने के अलावा कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है। पुलिस रिपोर्ट यह मान सकती है कि कोई अपराध किया गया है या नहीं किया गया है और इसे मजिस्ट्रेट के समक्ष रखने पर उससे अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने का अनुरोध करने पर कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान ले लिया है।

(पैरा 10)

एमएसटी. इदो बनाम गैंदा सिंह आदि ए.आई.आर. 1952 पेप्सू 38.
हरबीर सिंह बनाम राज्य और दूसरा, ए.आई.आर. 1952 पेप्सू 29.

खारिज

24 सितंबर, 1979 को माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एस. बैंस द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए मामला एक डिवीजन बेंच को भेजा गया था- मामले में शामिल कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न- बड़ी बेंच जिसमें शामिल है माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया, एवं माननीय श्री.

न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी ने आखिरकार 1 नवंबर 1979,को मामले का फैसला योग्यता के आधार पर किया।

श्री राम सरन भाटिया, के आदेश के संशोधन के लिए धारा 401 के साथ धारा 397(3) सीआरपीसी के तहत याचिका | अतिरिक्त न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी ने आखिरकार 1 नवंबर को मामले का फैसला सुनाया।
श्री वी. पी. चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सफीदों, दिनांक 12 मई 1978 को धारा 467, 468, 420 के तहत आरोपियों को तलब किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 474, 471/120-बी |

याचिकाकर्ता के वकील के.सी. जैन।

प्रतिवादी की ओर से पी.एस. जैन, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 4 के लिए वकील एम. आर. अग्निहोत्री

निर्णय

न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी,

(1) इस याचिका में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जींद का 16 फरवरी, 1979 का एक आदेश, जिसके तहत उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सफीदों के 12 मई, 1978 के आदेश को रद्द कर दिया और कार्यवाही रद्द कर दी। चुनौती दी गई. शुरुआत में मामला ए.एस. बैंस जे. के सामने आया, जिन्होंने एमएसटी में निर्धारित अनुपात की शुद्धता पर संदेह किया। इडौ बनाम गैंदा सिंह, आदि[1], यह पाते हुए कि मामला कठिनाई से मुक्त नहीं है, मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की सिफारिश की गई। इसी तरीके से यह मामला हमारे सामने रखा गया है.

(2) एमएसटी इडो में निर्धारित नियम का मामला (सुप्रा) निम्नलिखित स्थिति में नियोजित किया गया: -

[1] ए.आई.आर. 1952 पेप्सू 38

(3) ग्राम गोगरीपुर निवासी नसीब सिंह ने पुलिस थाना सफीदों में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 173, दिनांक 18 अगस्त 1977 दर्ज कराई, जिसमें शिकायत की गई कि वर्तमान उत्तरदाताओं द्वारा जाली वसीयत बनाई गई है, जिसे कथित तौर पर एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। भरथा की मृत्यु 20/21 सितंबर, 1976 की दरमियानी रात को हो गई थी। मामन, प्रतिवादी नंबर 1, मृतक भरथा का भाई था और वह जाली वसीयत के तहत उत्तराधिकारियों का पिता था। शीतल प्रकाश प्रतिवादी याचिका-लेखिका थीं; जसवन्त सिंह उप-रजिस्ट्रार थे और श्री जय देव सिंह, वकील, वसीयत बनाने में अन्य सहयोगी और सह-साजिशकर्ता थे ताकि श्रीमती को वंचित किया जा सके। शांति और श्रीमती. गोगरी, मृतक भरथा की पुत्रियों को प्राकृतिक उत्तराधिकार का लाभ। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों महिलाएं उनकी बहुएं थीं। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद धारा 169, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया।
इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पहले मुखबिर और उपरोक्त श्रीमती को एक नोटिस भेजा। शांति और श्रीमती. गोगरी, अगर उन्हें मामले को रद्द करने के प्रस्ताव पर कोई शिकायत थी। इन व्यक्तियों की उपस्थिति पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने उनके बयान दर्ज किए और बारू और सतर्कता निरीक्षक भजन सिंह के भी बयान दर्ज किए। फिर उसने अपने आदेश, दिनांक 12 मई, 1978 ने वर्तमान उत्तरदाताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 467, 468, 420, 474, 471 के तहत आरोपों का जवाब देने के लिए आरोपी व्यक्ति के रूप में बुलाने का निर्देश दिया। उक्त आदेश को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जींद के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा पुनरीक्षण में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई, जिन्होंने 16 फरवरी, 1979 को अपने फैसले के तहत इसे रद्द कर दिया। और सुझाव दिया कि उनके निर्णय के बावजूद, पहला मुखबिर एक निजी शिकायत दर्ज कर सकता है यदि यह कानून के तहत स्वीकार्य हो। मुख्य कारण जो उन पर भारी पड़ा वह एमएसटी में निर्णय को ध्यान में रखते हुए था। इदो बनाम गैंदा सिंह, आदि (1 सुप्रा), जिसमें उसी न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसे हरबीर सिंह बनाम राज्य और अन्य[2] के रूप में रिपोर्ट किया गया था, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास समन करने की कोई शक्ति नहीं थी। जब जांच अधिकारी ने मामले को रद्द करने के लिए रिपोर्ट बनाई थी तो प्रतिवादियों पर आरोप लगाया। सोना देवी बनाम राज्य, आदि[3] से भी इस दृष्टिकोण का समर्थन मांगा गया था। पहले मुखबिर द्वारा अतिरिक्त संशोधन दायर किया गया है जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है जो एमएसटी पर आधारित है। इडो का मामला (सुप्रा) और इसलिए हमें इसके आधार की शुद्धता की जांच करने की आवश्यकता है।

(4) सूचक-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दावा किया कि यह मामला पूर्ण नहीं था और अभिनंदन झा और अन्य बनाम दिनेश मिश्रा[4] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसका अंततः निपटारा

---

[2] ए.आई.आर. 1952 पेप्सू 29
[3] 1972 करंट लॉ जर्नल 955
[4] ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 117

हुआ। उनके आधिपत्य ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय XIV के ऑपरेटिव क्षेत्र में और अध्याय XV में आने वाली धारा 190 की भी विस्तृत जांच की है। यह अनुभाग 'कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें' शीर्षक और उप-धारा (1) के अंतर्गत पाया जाना चाहिए, जैसा कि 1898 के संहिता में और 1973 की संहिता के तहत भी इस प्रकार है: -

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1898: 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान.

(1) इसके बाद दिए गए प्रावधानों को छोड़कर कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है: -

(ए) उन तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं;

(बी) मेरे पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर;

(सी) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या अपने स्वयं के ज्ञान या संदेह पर, कि ऐसा अपराध किया गया है

(5) अभिनंदन झा के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने से पहले, पुराने और नए कोड की धारा 190 का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हो जाता है। उप-धारा (1) के खंड (बी) और (सी) में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए हैं। जाहिर तौर पर किसी खास मकसद से भाषा में बदलाव किया गया है.

(6) विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में इस प्रावधान पर इस प्रकार टिप्पणी की थी:-

"15.74 पहली नज़र में, बेशक 'पुलिस रिपोर्ट' और "पुलिस-अधिकारी की रिपोर्ट" के बीच अर्थ में अंतर मामूली लग सकता है, लेकिन आधिकारिक निर्णय यह दिखाते हैं अभिव्यक्ति 'पुलिस रिपोर्ट', जो वास्तव में 1923 से पहले धारा 190(1) के खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति थी, का एक तकनीकी अर्थ है, जो संहिता की धारा 173 के तहत एक जांच अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट तक सीमित है। . ऐसी जांच केवल संज्ञेय अपराध की हो सकती है, या यदि इसे गैर-संज्ञेय अपराध बनाया जाता है, तो इसे धारा 155 के तहत आवश्यक मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ होना चाहिए। इसलिए, हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि मजिस्ट्रेट आसानी से अंतर करने में सक्षम हों किसी अन्य प्रकार के मामले की पुलिस रिपोर्ट पर मामला स्थापित किया गया; और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, हम प्रस्ताव करते हैं, कि अभिव्यक्ति 'पुलिस रिपोर्ट' को संहिता में ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, और परिभाषा को न्यायिक निर्णयों का पालन करना चाहिए, इसे धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट तक

सीमित करना चाहिए। उन्हीं कारणों से, हम प्रस्ताव करते हैं धारा 190 के खंड (बी), उप-धारा (1) में केवल 'पुलिस रिपोर्ट' का उल्लेख होना चाहिए, पुलिस अधिकारी द्वारा अन्य प्रकार की रिपोर्ट को शिकायतों के रूप में माना जाना चाहिए। हम पहले ही धारा 4 में निहित 'शिकायत' की परिभाषा में आवश्यक मौखिक परिवर्तन का प्रस्ताव कर चुके हैं।

(7) उस उद्देश्य और कारण को पूरा करने के लिए धारा 190 की उपधारा (1) का वर्तमान खंड (बी) अस्तित्व में आया है। परिणाम के रूप में, अभिव्यक्ति 'पुलिस रिपोर्ट' को अब नई संहिता की धारा 2(आर) में उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"'पुलिस रिपोर्ट' का अर्थ धारा 173 की उपधारा (2) के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट है।"

धारा 173 की उपधारा (2) के अर्थ में 'पुलिस रिपोर्ट' अब केवल एक रिपोर्ट तक ही सीमित होने पर, 'शिकायत' शब्द में आवश्यक रूप से बदलाव होना चाहिए। यह परिवर्तन उक्त संहिता की धारा 2(डी) में दी गई 'शिकायत' की एक नई परिभाषा से प्रभावित हुआ है। यह पढ़ता है:

"शिकायत' का अर्थ मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया कोई भी आरोप है एक मजिस्ट्रेट को, इसके तहत कार्रवाई करने की दृष्टि से कोड, कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्पष्टीकरण: किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट, जो जांच के बाद, गैर-संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, एक शिकायत मानी जाएगी। और जिस पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है, उसे शिकायतकर्ता माना जाएगा।"

(8) धारा 190 की धारा (1) के खंड (सी) में किए गए परिवर्तन के संबंध में, अभिव्यक्ति 'या संदेह' को आसानी से छोड़ा जा सकता है। इस चूक का उद्देश्य और कारण भी विधि आयोग की उपरोक्त 41वीं रिपोर्ट से निम्नलिखित शब्दों में संकेत मिलता है:-

"15.79। यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 190 यह प्रावधान करती है कि कुछ मजिस्ट्रेट कुछ शर्तों को पूरा करने पर अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं। कई बार अदालतों में इस पर बहस की गई है और तर्क को स्वीकार किया गया है, कि, 'हो सकता है' शब्द के उपयोग के बावजूद 'एक मजिस्ट्रेट बाध्य है। यदि उसके सामने उचित शिकायत है, या उचित पुलिस रिपोर्ट है तो किसी अपराध का संज्ञान लें। कई बार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में एक हालिया मामले में देखा गया है कि एक मजिस्ट्रेट के पास इस संबंध में पर्याप्त विवेक है और यदि किसी पुलिस रिपोर्ट को देखने पर वह कहता है कि पूरी तरह से जांच नहीं की

गई है, तो वह बिना संज्ञान लिए आगे की जांच का आदेश दे सकता है, इसलिए, हम यह मानते हैं कि एक मजिस्ट्रेट के पास इस संबंध में एक निश्चित विवेक है, लेकिन चूंकि यह विवेक न्यायिक है प्रकृति, यह अपने दायरे में सीमित है, और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए, हम अनुभाग की भाषा को परेशान करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।"

(9) उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो विधि आयोग के विचार में शायद अभिनंदन झा का मामला (सुप्रा) था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (पुरानी) की धारा 190 की उप-धाराओं (बी) और (सी) के दायरे पर विचार करते हुए, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का आधिपत्य। निम्नानुसार मनाया गया:-

"इन दो अपीलों में, जो बिहार राज्य से हैं। धारा 169 के तहत रिपोर्ट को 'अंतिम रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित किया गया है। अब, सवाल यह है कि रिपोर्ट प्राप्त करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा वास्तव में क्या किया जाना चाहिए, धारा 173 के तहत, विचार करना होगा। वह रिपोर्ट धारा 170 के तहत आने वाले मामले के संबंध में हो सकती है, या धारा 169 के तहत आने वाले मामले के संबंध में हो सकती है। हम पहले ही धारा 190 का उल्लेख कर चुके हैं, जो कि समूह में पहला खंड है। 'कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें' शीर्षक वाले अनुभाग। इस अनुभाग के उप-खंड (1) में शामिल किया जाएगा धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट भेजी गई। धारा 190 की उप-धारा (1) में 'किसी भी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है' शब्दों का उपयोग, हमारी राय में, 'न्यायिक विवेक' का प्रयोग करता है, और मजिस्ट्रेट, जो धारा 173 के तहत रिपोर्ट प्राप्त करने पर, उक्त रिपोर्ट पर विचार करना होगा और न्यायिक रूप से निर्णय लेना होगा कि अपराध का संज्ञान लिया जाए या नहीं।इससे यह पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट पुलिस की इस राय को मानने के लिए बाध्य है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने का मामला है। मजिस्ट्रेट यह विचार करने के लिए स्वतंत्र है कि रिपोर्ट में बताए गए तथ्य संज्ञान लेने के लिए अपराध नहीं बनते हैं या वह यह विचार कर सकता है कि किसी आरोपी को मुकदमे में डालने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इनमें से किसी भी आधार पर, पुलिस की राय के बावजूद, किसी अपराध का संज्ञान लेने से इनकार करना मजिस्ट्रेट के लिए पूरी तरह से उचित होगा। दूसरी ओर, यदि मजिस्ट्रेट रिपोर्ट से सहमत है, जो कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र है, तो कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसके पास धारा 190(1)(के तहत अपराध का संज्ञान लेने का पूरा अधिकार क्षेत्र होगा। बी) संहिता का. यह स्थिति तब होगी, जब रिपोर्ट, धारा 173 के तहत, एक आरोप-पत्र है।

फिर सवाल यह है कि स्थिति क्या है, जब मजिस्ट्रेट धारा 173 के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, कि किसी आरोपी को मुकदमे के लिए भेजने का कोई मामला नहीं बनता है, जो रिपोर्ट, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं- प्रश्नगत क्षेत्र में निर्दिष्ट को 'अंतिम रिपोर्ट' के रूप में बुलाया जाता है? उन मामलों में भी, यदि मजिस्ट्रेट उक्त रिपोर्ट से सहमत है, तो वह अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और कार्यवाही बंद कर सकता है। लेकिन ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जब अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने पर मैजिस्ट्रेट यह विचार कर सकता है कि पुलिस द्वारा बनाई गई राय

पूर्ण और संपूर्ण जांच पर आधारित नहीं है, जिस स्थिति में, हमारी राय में, मजिस्ट्रेट के पास आगे की जांच करने के लिए धारा 158(3) के तहत पुलिस को निर्देश देने का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा। अर्थात यदि मजिस्ट्रेट को लगता है. अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, कि जांच असंतोषजनक है, या अधूरी है, या आगे की जांच की गुंजाइश है, मजिस्ट्रेट के पास अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करने और पुलिस को धारा 156(3) के तहत आगे की जांच करें निर्देश देने का अधिकार होगा। पुलिस, ऐसी आगे की जांच के बाद, उनके द्वारा की गई आगे की जांच के आधार पर, आरोप-पत्र दाखिल कर सकती है, या, फिर से एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। यदि अंततः, मजिस्ट्रेट यह राय बनाता है कि अंतिम रिपोर्ट में दिए गए तथ्य अपराध बनते हैं, तो वह धारा 190(1)(बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है, विपरीत राय के बावजूद नहीं। पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट में व्यक्त किया। इस संबंध में, संहिता की धारा 169 के प्रावधान प्रासंगिक हैं। वे विशेष रूप से प्रदान करते हैं कि भले ही, जांच पर, एक पुलिस अधिकारी, या अन्य जांच अधिकारी की राय है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई मामला नहीं है, वह आरोपी को रिहा करते समय, उससे एक बांड लेने के लिए बाध्य है। यदि आवश्यक हो तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट की आकस्मिक स्थिति को पूरा करने के लिए है, जब वह जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करता है, और न्यायिक रूप से पुलिस से अलग दृष्टिकोण अपनाता है।

*

यदि मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा बनाई गई राय से सहमत नहीं है, तो रिपोर्ट को स्वीकार करने का मजिस्ट्रेट पर निश्चित रूप से कोई दायित्व नहीं है। उन परिस्थितियों में, यदि उसे अभी भी संदेह है कि कोई अपराध किया गया है, तो वह पुलिस की राय के बावजूद, संहिता की धारा 190(1)(सी) के तहत संज्ञान लेने का हकदार है | हमारी राय में उस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना है कि अपराध बिना दंड के न रहें और न्याय तब भी लागू किया जा सके जहां व्यक्तिगत रूप से पीड़ित व्यक्ति मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हैं, या पुलिस भी। लापरवाही से या वास्तविक त्रुटि के माध्यम से, अपराध का गठन करने वाले तथ्यों को स्थापित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहें। इसलिए, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए जादूगर को बहुत व्यापक शक्ति प्रदान की जाती है, न कि केवल तब जब उसे किसी तीसरे व्यक्ति से अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बल्कि वहां भी जहां उसे जानकारी हो या संदेह हो कि अपराध किया गया है। धारा 190(1)(सी) के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है। इस आधार पर कि, अंतिम रिपोर्ट पर उचित ध्यान देने के बाद और उसके सामने रखे गए पुलिस रिकॉर्ड से उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई अपराध किया गया है। इसलिए, ये परिस्थितियाँ पुलिस से आरोप-पत्र माँगने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को भी स्पष्ट रूप से नकारात्मक कर देंगी, जब उन्होंने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो।"

(10) नए कोड के तहत भी, सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा निर्धारित कानून अपवादहीन बना हुआ है, सिवाय इसके कि अब मजिस्ट्रेट के लिए धारा 190(1)(सी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेना खुला नहीं है। संदेह के आधार पर नया कोड. वह संज्ञान केवल मजिस्ट्रेट की जानकारी पर ही लिया जा सकता है। वह ज्ञान मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से या उसके बिना भी प्राप्त कर सकता है ताकि नई संहिता की धारा 190(1)(सी) के तहत संज्ञान की नींव रखी जा सके। यही उद्देश्य नई संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत भी प्राप्त किया जा सकता है, जब धारा 173(2) के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह निर्दिष्ट करना होता है कि क्या कोई अपराध प्रतीत होता है अन्य विवरणों का उल्लेख करने के अलावा प्रतिबद्ध किया गया। पुलिस रिपोर्ट यह मान सकती है कि कोई अपराध किया गया है या नहीं किया गया है और इसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष रखने पर उससे अपने न्यायशास्त्र को लागू करने का अनुरोध किया जा सकता है! इस पर ध्यान दें, यह माना जाता है कि मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान ले लिया है।

(11) एमएसटी में पेप्सू उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। इदो का मामला (सुप्रा) और हरबीर सिंह का मामला (सुप्रा) इस आशय का है कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(सी) का सहारा नहीं ले सकते हैं और सूचना आपूर्ति पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं, जो कि आदेश के विपरीत है। अभिनंद झा के मामले में सुप्रीम कोर्ट (सुप्रा) लेकिन कानून में संशोधन के मद्देनजर, एमएसटी में वें अनुपात। इडो का मामला आंशिक रूप से इस हद तक नया हो गया है कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर नई संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत संज्ञान नहीं ले सकता है। एमएसटी. धारा 190 के खंड (बी) ओ उप-धारा (1) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति के संबंध में इडो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अभिनंदन झा के मामले और हालिया संशोधन के मद्देनजर सही कानून नहीं बनाता है। मजिस्ट्रेट उतना असहाय नहीं है जितना उस मामले में चोपड़ा जे. ने माना था या हरबीर सिंह के मामले में डिवीजन बेंच ने किया था। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक घोषणा और संशोधित कानून के मद्देनजर, एमएसटी में दिए गए निर्णय। इदो बनाम गींदा सिंह आदि (1 सुप्रा), और हरबीर सिंह बनाम राज्य और दूसरा, (2 सुप्रा), को खारिज कर दिया जाना चाहिए और अब यह अच्छा और लागू कानून नहीं है।

(12) उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने कहा कि यह कानून का आदेश है, और अभिनंदन जना के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निर्धारित किया गया है, कि संज्ञान लेने पर मजिस्ट्रेट द्वारा पीआर को खारिज कर दिया जाना चाहिए। धारा 190(1)(सी) एक शिकायत है। उस उद्देश्य के लिए यह तर्क दिया गया कि यह इंगित किया जाना चाहिए कि मैजिस्ट्र लेक ने इस मामले पर कब संज्ञान लिया। देवराप लक्षनमीनारायण रेड्डी और उनके बनाम नारायण रेड्डी और अन्य (5) पर भरोसा रखा गया था। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है या नहीं लिया है, यह स्पष्ट रूप से विशेष मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें मामले को शुरू करने की मांग की गई है और मजिस्ट्रेट द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई की प्रकृति, यदि कोई हो, शामिल है। मौजूदा मामले में, जब मामले को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के तहत

मजिस्ट्रेट के सामने मामला लाया गया और उन्होंने विवेक के इस्तेमाल पर जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया और जांच करने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि शिकायतकर्ता और अन्य लोगों ने अपना दिमाग लगाया और मामले का संज्ञान लिया। लॉगनिज़ांस की शुरुआत कहां से हुई, इसका सटीक समय या चरण निर्धारित करना पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा। पुलिस द्वारा उन्हें सौंपी गई रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी, यदि शिकायत के तरीके से आगे बढ़ती है, तो प्रारंभिक साक्ष्य की जांच की आवश्यकता होती है और यह वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी-प्रतिवादियों को बुलाने से पहले किया गया है। . वह आगे से प्रक्रिया का पालन करेंगे उसके समक्ष अभियुक्त-प्रतिवादियों की उपस्थिति पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के तहत उसे आदेश दिया गया है। मुकदमा कानून के अनुसार अपना काम करेगा। एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है और इसलिए उसे रद्द किया जाता है।

(13) परिणामस्वरूप, याचिका की अनुमति दी जाती है, मजिस्ट्रेट ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में आगे बढ़ते हैं। पार को उनके वकील के माध्यम से 22 नवंबर, 1979 को ट्रायल सी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा